

हथकरघा को नयी पहचान दिला रही योगी सरकार, बुनकरों का बड़ा उत्साह

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर संत कबीर राज्यस्तरीय पुरस्कार समारोह

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर राज्यस्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के बुनकरों और लाभार्थियों को सम्मानित किया। शुक्रवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में मुख्यमंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार और चेक प्रदान किए। कार्यक्रम में सम्मान पाने वाले बुनकरों ने इसे अपने लिए गौरव का क्षण बताते हुए योगी सरकार के प्रति आभार जताया। बनारसी साड़ियों का काम करने वाले वाराणसी के जमालुद्दीन ने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का कार्यक्रम उनके लिए गौरवान्वित करने वाला है हथकरघा क्षेत्र को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार प्रयासरत है। जमालुद्दीन ने बताया कि 2017 के बाद इस क्षेत्र में कई बेहतर कार्य हुए हैं और पहली बार उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। सीतापुर के बुनकर अकील अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किए जाने से उन्हें बेहद प्रसन्नता हुई है। योगी सरकार आने के बाद प्रदेश में अनेक बदलाव हुए हैं और इन्हीं बदलावों का परिणाम है कि बुनकर बेहतर



तरीके से अपना काम आगे बढ़ा पा रहे हैं। वाराणसी के साड़ी बुनकर प्यारेलाल ने कहा कि सीएम योगी बुनकर समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं। रोजगार और कारोबार को आगे बढ़ाने के प्रयासों से उन्हें लाभ मिल रहा है। समय पर आर्थिक सहायता मिलने से काम को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है और सम्मान मिलने से उनका मनोबल भी बढ़ा है। ललितपुर की मीराबाई ने कार्यक्रम में बुलाकर सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इटावा की बिनाई कारीगर सोनी ने कहा कि सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसका सकारात्मक असर उनके

काम और तरक्की पर दिखाई दे रहा है। हाथरस के रूप किशोर ने कहा कि सीएम योगी का विजन बुनकरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। 2017 के बाद हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र की उन्नति के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। टांडा के शाहनवाज अहमद ने बताया कि वे गमछ, साड़ी और दुपट्टा बनाने का काम करते हैं। हस्तशिल्पकारों के लिए किए जा रहे प्रयासों से काम को मजबूती मिल रही है। वहीं सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बुनकरों को आगे बढ़ने का भरोसा और मजबूती मिल रही है।

कांवड़ शिविरों में सात्विक स्वाद के साथ हाईटेक सेवा बिना प्याज-लहसुन के देसी से लेकर चाइनीज व्यंजन तक मिल रहे

विशेष संवाददाता (vol)

मेरठ। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में इस बार सेवा, स्वच्छता और आधुनिक व्यवस्थाओं का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मेरठ में कांवड़ मार्ग पर लगाए गए शिविरों में शिवभक्तों के स्वागत के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो किसी बड़े आयोजन से कम नहीं हैं।

सात्विक परंपरा को बनाए रखते हुए श्रद्धालुओं को बिना प्याज-लहसुन के देसी व्यंजनों के साथ आधुनिक स्वाद भी परोसे जा रहे हैं। शिविरों में पास्ता, पिज्जा, नूडल्स, मोमोज और मंचूरियन जैसे व्यंजन भी कांवड़ियों के लिए उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत प्रशासनिक अधिकारी लगातार शिविरों का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं।

कांवड़ियों के लिए पूरे दिन के भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है। सुबह चाय, बिस्किट, पोहा और जलेबी से दिन की शुरूआत होती है। नाश्ते में समोसा, कचौड़ी,

भरवारा आरओबी निर्माण का रास्ता साफ भूमि अधिव्रहण की प्रक्रिया फिर से होगी

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोमतीनगर स्थित भरवारा रेलवे क्रॉसिंग पर लंबे समय से प्रस्तावित रेल उपरिगामी सेतु (आरओबी) के निर्माण का रास्ता साफ करते हुए राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के अहम चरण दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने माना कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अधिग्रहण प्रक्रिया में गंभीर प्रक्रियामय खामियां बरती गई हैं।

न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा-11 के तहत जारी प्रारंभिक अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया कि भूमि अधिग्रहण से किसी परिवार को विस्थापन नहीं होगा, जबकि सामाजिक प्रभाव आकलन (सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट) रिपोर्ट इससे अलग स्थिति दर्शाती है। अदालत ने इसे बिना समुचित विचार किए लिया गया निर्णय माना

और कहा कि इसी कारण धारा-19 की अधिसूचना सहित बाद की समस्त अधिग्रहण कार्रवाई विधिसम्मत नहीं ठहराई जा सकती। खंडपीठ ने कहा कि एक ओर आरओबी का शीघ्र निर्माण जनहित में आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित भूमि स्वामियों के वैधानिक अधिकारों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर धारा-11 की अधिसूचना में संशोधन (कोरिजेंडम) जारी करे या फिर नई अधिसूचना जारी कर कानून के अनुसार पूरी अधिग्रहण प्रक्रिया दोबारा शुरू करें। अदालत ने अधिकारियों को छह माह के भीतर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

साथ ही, आरओबी परियोजना की प्रगति पर निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) जनहित याचिका दर्ज करने का आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी कहा है।

रालोद को झटका, प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने दिया इस्तीफा

लखनऊ। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को बड़ा झटका लगा है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी रामाशीष राय ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं, रालोद के शीर्ष नेतृत्व ने नये प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ऐश्वर्य राज सिंह को नियुक्त किया है। फिलहाल श्री राय ने इस्तीफे में अपनी ही पार्टी की नीतियों पर इशारों में कई आरोप लगाये हैं। किसानों और नौजवानों की बात कहते हुए उनकी समस्याओं को उठाया है। जय प्रकाश नारायण और अचल बिहारी जाजपेयी के अह्दाओं की चर्चा करते हुए लिखा कि आज संविधान, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे प्रहार से लोकतंत्र खतरे में है। रामाशीष राय इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। चर्चा है कि वह सपा में जा सकते हैं। अमला विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी है। रामाशीष ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि मैं राजनीति में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण

● ऐश्वर्य राज सिंह बने रालोद के नये प्रदेश अध्यक्ष

क्रांति आंदोलन से प्रेरित होकर जुड़ा था। उस समय भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण और शासन-प्रशासन की जवाबदेही जैसे प्रश्न राष्ट्रीय चिंता के विषय थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हुए व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना देश के सामने रखा था, वह आज भी अधूरा प्रतीत होता है।

देवरिया से चुनाव लड़ने की चर्चा : कुछ दिनों पहले ही जयंत चौधरी ने अनुपम मिश्रा को रालोद का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था। तभी से माना जा रहा था कि डा. राय पार्टी छोड़ सकते हैं। उनके सपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि देवरिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ने की तैयारी है। ऐसे में कांग्रेस में भी जाने की चर्चा है। हालांकि उन्होंने अभी इस पर कोई भी जानकारी साझा नहीं की है।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से देश के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रदेश में 8 बड़ी कंपनियां 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने जा रही हैं। इन परियोजनाओं से 25 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एचसीएल-फॉक्सकॉन, अवाडा इलेक्ट्रो, एंबर एंटरप्राइजेज, एसएईएल सोलर, ओरियाना पावर, सीईएससी ग्रीन पावर, आईबी सोलर और एसेंट के सिकंटे जैसी कंपनियां गौतमबुद्ध नगर में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने या अपने निवेश का विस्तार करेंगी। प्रदेश सरकार का कहना है कि उद्योग-अनुकूल नीतियों, पारदर्शी शासन, बेहतर कानून व्यवस्था, विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे और निवेशकों को समयबद्ध सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था से उत्तर प्रदेश देश-विदेश की कंपनियों की पसंद बन रहा है।

4677 नये ट्रांसफार्मरों से बदलेगी 19 जिलों की बिजली व्यवस्था

बार-बार ट्रांसफार्मर फुंकने की समस्या होगी कम, लेसा समेत मध्यांचल के सभी जिलों में जल्द लगेंगे

समरेश पति त्रिपाठी

लखनऊ। गर्मी और ओवरलोडिंग के दौरान बार-बार ट्रांसफार्मर फुंकने से जूझ रहे बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) ने लेसा के चारों जोन सहित 19 जिलों की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुल 4677 नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। ट्रांसफार्मरों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही इनकी आपूर्ति शुरू होने के साथ संबंधित जिलों में स्थाना कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। विभाग का मानना ​​है कि नए ट्रांसफार्मर लगने से ओवरलोडिंग की समस्या में कमी आएगी, ट्रांसफार्मर फुंकने की घटनाएं घटेंगी और उपभोक्ताओं को अधिक भरोसेमंद बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। योजना के तहत सबसे अधिक ध्यान छोटे क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मरों पर दिया गया है, ताकि तेजी से बढ़ रहे बिजली भार को संतुलित किया जा सके। वर्तमान में कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने अथवा क्षमता से अधिक

संगठन की मजबूती व जनभागीदारी से मिलेगी जीत

मंत्री ने विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजाति आयोग के गठन पर मुख्यमंत्री का निषाद समाज की ओर से जताया आभार

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। निषाद पार्टी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर लखनऊ मंडल के पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. संजय कुमार निषाद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव संगठन की एकजुटता, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के विश्वास का चुनाव होगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से बृ्थ स्तर तक संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा पार्टी की नीतियों का मछुआ समाज के घर-घर तक पहुंचाने का कार्य करें।

उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी सामाजिक न्याय, समान भागीदारी और वंचित, शोषित एवं पिछड़े समाज के अधिकारों की लड़ाई निरंतर लड़ती रही है। प्रदेश



सरकार द्वारा समाज के सर्वांगीण विकास एवं अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए किए जा रहे कार्यों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रत्येक पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में नियमित जनसंपर्क अभियान चलाए, नए कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़े तथा बृ्थ और सेक्टर स्तर पर संगठनात्मक संरचना को पूर्ण रूप से सुदृढ़ करें। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से पूर्ण समर्पण, अनुशासन और टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में संगठन

जनजातियों को उनका सम्मान और अधिकार दिलाने का संघर्ष आज का नहीं, बल्कि दशकों पुराना है। उन्होंने स्वयं भी लंबे समय से इन समाजों को उनका संवैधानिक एवं सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए निरंतर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू समुदायों की लगभग 193 जातियां निवास करती हैं।

डॉ. संजय कुमार निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजाति आयोग के गठन का निर्णय इन समुदायों के सम्मान, अधिकारों और समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जिन समुदायों की उपेक्षा की, आज उन्हें सम्मान और अधिकार दिलाने का कार्य वर्तमान सरकार कर रही है। इसके लिए निषाद समाज सहित सभी विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू समुदाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

रवींद्रनाथ टैगोर और स्व.मानसी दत्ता को दी श्रद्धांजलि

लखनऊ। बंगे नागरिक समाज द्वारा राष्ट्रगान 'जन गण मन' के रचयिता, नोबेल पुरस्कार विजेता एवं भारतीय साहित्य के युगपुरुष गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को किया गया। कार्यक्रम में रालोद व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने लखनऊ स्थित गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके साहित्य, शिक्षा, मानवता और राष्ट्र के प्रति अमूल्य योगदान को स्मरण किया। इस अवसर पर बंगे नागरिक समाज की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की अनुयायी स्वर्गीय मानसी दत्ता की पुण्यतिथि पर भी श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और उनके सामाजिक योगदान को याद किया गया।

अखिलेश से मिले अभ्यर्थी, अतिरिक्त अवसर देने की उठायी मांग



लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीसीएस, आरओ/एआरओ एवं बीईओ परीक्षा की तैयारी कर रहे उन अभ्यर्थियों से मुलाकात की, जो कोरोना काल, पाठ्यक्रम में बदलाव और नई सेवा भर्ती नियमावली के कारण आयु सीमा पार कर चुके हैं।

इन युवाओं की मांग है कि उनके साथ-न्याय करते हुए पीसीएस परीक्षा में दो अतिरिक्त अवसर तथा आरओ/एआरओ और बीईओ में एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाए। युवाओं ने जापन देकर कहा कि कोरोना काल (2019-21) में पढ़ाई और

परीक्षाओं की तैयारियां प्रभावित हुईं। इसके बाद पीसीएस के पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव (2023-25) हुआ जिससे अभ्यर्थियों को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ी। अब नई सेवा भर्ती नियमावली 2026 का लाभ भी आयु सीमा पार कर चुके इन अभ्यर्थियों को नहीं मिल पा रहा है। युवाओं के वर्षों के परिश्रम और उनके भविष्य को देखते हुए उनकी मांगों को पूरा करे सरकार।

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। युवाओं के संघर्ष में सपा उनके साथ खड़ी है।

आरटीआई में भ्रामक सूचना और दो साल की देरी पड़ी भारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब और भ्रामक सूचना देने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने कानपुर देहात के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक को अपीलकर्ता को 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। राज्य सूचना आयोग स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता ने यह आदेश पारित किया। यह मामला सीमा सिंह बनाम जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अपर पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात से संबंधित है। आयोग के अनुसार, अपीलकर्ता ने 4 अक्टूबर 2023 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देकर थाना रूमा में दर्ज एक आपराधिक प्रकरण से संबंधित चार बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इसमें लेखपाल अशोक कुमार की गिरफ्तारी, गिरफ्तारी से जुड़े अभिलेख और एक वाहन से संबंधित सूचनाएं शामिल थीं। हालांकि, जन सूचना अधिकारी ने 1 नवंबर 2023 को जवाब देते हुए सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) (जे) और धारा 11 के तहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने प्रथम और फिर द्वितीय अपील सूचना आयोग में दायर की। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि मांगी गई सूचनाओं से संबंधित अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध थे और नियमानुसार उपलब्ध कराए जा सकते थे। आयोग ने माना कि प्रारंभिक स्तर पर दी गई सूचना भ्रामक थी, जिससे अपीलकर्ता को यह आभास हुआ कि जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। बाद की प्रक्रिया में वही सूचना उपलब्ध कराई गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि प्रारंभिक जवाब उचित नहीं था। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि सूचना उपलब्ध कराते में लगभग दो वर्ष का अनावश्यक विलंब हुआ, जिससे अपीलकर्ता को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर आयोग ने 20 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया।

संक्षेप

11 कोनिकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा तैयारियों में जुटे भाजपाई

भटनी (देवरिया)। भारतीय जनता पार्टी भटनी मंडल की मासिक बैठक शुक्रवार को बाई पास रोड स्थित एक विद्यालय के परिसर में मंडल अध्यक्ष रोहित मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन तिरंगा यात्रा के संयोजक एवं मंडल उपाध्यक्ष सत्यव्रत मिश्रा ने किया। बैठक में आगामी 11 अगस्त को आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक के मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी त्रिगुणायक विश्वकर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रत्येक कार्यकर्ता घर-घर तक राष्ट्रप्रेम का संदेश पहुंचाए तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुशासन, संगठन की मजबूती और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का किया।बैठक में निर्णय लिया गया।

परेड में एसपी ने परखी पुलिस बल की कार्यक्षमता

जिला संवाददाता

ललितपुर। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स में आयोजित साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी लेकर पुलिस बल की कार्यक्षमता, अनुशासन एवं व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्रिल, टर्नआउट, ड्रेस कोड, शारीरिक दक्षता और सामूहिक

पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं का किया निरीक्षण

तालमेल का बारीकी से अवलोकन किया तथा आवश्यक ड्रिल अभ्यास कराते हुए अनुशासन, समयपालन और कर्तव्यनिष्ठा के साथ दायित्व का निर्वहन करने के निर्देश दिए। परेड निरीक्षण के बाद एसपी ने रिजर्व पुलिस लाइन्स परिसर स्थित क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार एवं स्टोर रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखों के समुचित रख-रखाव, साफ-सफाई, उपलब्ध संसाधनों एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने परिवहन शाखा का निरीक्षण कर पुलिस वाहनों की साफ-सफाई, संचार व्यवस्था, वायरलेस सेट, जीपीएस ट्रैकर, टैब, मोबाइल एवं अन्य आपातकालीन उपकरणों की कार्यशीलता का परीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि

छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की समयबद्ध एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: डीएम

बाराबंकी। कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की। बैठक में

●**डीएम ने की वित्तीय वर्ष 2026–27 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा**

जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र छात्र-छात्राओं को समय पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की निर्धारित समय-सारणी के अनुसार मास्टर डाटा लॉक, ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन,

समाज के हर वर्ग को मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ: राज्यमंत्री

तहसील पाली में सहरिया संतृप्तीकरण कार्यक्रम में एक साथ सैंकड़ों लोगों के बनाये गये आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र

जिला संवाददाता

ललितपुर। बुन्देलखण्ड क्षेत्र का ललितपुर जनपद, जो अपनी प्राकृतिक सम्पदा के लिए जाना जाता है और प्रकृति के वरदान कही जाने वाली जड़ीबूटियों की उपलब्धता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जिला है, यहां के जंगलों में एक ऐसा समुदाय निवास करता है जो इन्हीं जड़ीबूटियों के सहारे अपना जीवन यापन करता है और

- वंचित समुदाय को सरकार की योजनाओं से जोड़कर आर्थिक व सामाजिक विकास है अभियान का लक्ष्य-जिलाधकारी**
- सरकारी योजनाओं से वंचित सहरिया समुदाय के उत्थान के लिए शुरु किया गया सहरिया संतृप्तिकरण अभियान**

दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए जड़ीबूटी औषधि उपलब्ध कराता है, लेकिन आज भी यह वर्ग आर्थिक और सामाजिक विकास से कोसो दूर है। इसका मुख्य कारण ये है कि सहरिया आदिवासी समुदाय के लोगों के पास उनके पहचान व जन्म सम्बन्धी कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इसी कारण वे शासन-प्रशासन की अनेकों महत्वपूर्ण व विकास परक योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, परन्तु अब ज्यादा

समय तक वे इन योजनाओं से वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश ने जनपद के सहरिया समुदाय को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए आर्थिक व सामाजिक उत्थान का संकल्प लिया है और इनके मूलभूत दस्तावेज बनाये जाने का अभियान शुरू किया है।

जिलाधिकारी के इस अभियान के तहत सहरिया लोगों और उनके बच्चों के जन्म व आधारकार्ड बनाये जाने के

- वंचित समुदाय को सरकार की योजनाओं से जोड़कर आर्थिक व सामाजिक विकास है अभियान का लक्ष्य-जिलाधकारी**
- सरकारी योजनाओं से वंचित सहरिया समुदाय के उत्थान के लिए शुरु किया गया सहरिया संतृप्तिकरण अभियान**

लिए गांव-गांव में कैम्प लगवाकर जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड बनाये जा रहे हैं।

साथ ही इन दस्तावेजों के बन जाने के बाद सहरिया समुदाय के लोगों को आवास, इञ्जतपर, राशन, विद्युत व नल कनेक्शन, कृषि और स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

इसी क्रम में आज शुक्रवार को जिलाधिकारी ने जनपद की जनजाति

बाराबंकी/ललितपुर

समाज के हर वर्ग को मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ: राज्यमंत्री

तहसील पाली में सहरिया संतृप्तीकरण कार्यक्रम में एक साथ सैंकड़ों लोगों के बनाये गये आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र

बाहुल्य पाली तहसील में सहरिया संतृप्तिकरण कार्यक्रम आयोजित कराया, जहां सैंकड़ों की संख्या में सहरिया लोगों के लिए जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार व अन्य प्रमुख सरकारी योजनाओं से सम्बंधित विभागों द्वारा कैम्प लगवाकर मौके पर ही उनके दस्तावेज तैयार कराये गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने तहसील पाली में पहुंचकर अलग-अलग स्टॉलों पर अपने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र व आधार कार्ड बनवाये, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लिए अपना पंजीकरण भी कराया।कार्यक्रम में उ0प्र0 शासन के राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ व जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय जनजाति समुदाय के लोगों से वार्ता की, उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर ही दूरभाष के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

जिलाधकारी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सहरिया संतृप्तिकरण अभियान के तहत जिले के ऐसे ग्रामों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां जनजाति आबादी अधिक संख्या में है, वहां पर आधार, जन्म-मृत्यु प्रमाण

एसपी संजीव कुमार बाजपेई ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा

ई-रिक्शा चालकों का सत्यापन, महिला सुरक्षा, कांवड़ यात्रा और अपराध नियंत्रण पर विशेष फोकस

ललितपुर। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई ने शुक्रवार को गूगल मीट के माध्यम से जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना एवं चोकी प्रभारियों के साथ कानून-

- मिशन सेफ प्यूचर के तहत स्कूल वाहनों की जांच तेज होगी**
- थाना प्रभारियों को दिए सख्त निर्देश**

व्यवस्था की समीक्षा बैठक की।बैठक में जनपद की सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, स्कूली बच्चों की सुरक्षा तथा आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर व्यापक समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी थाना एवं



पत्र, राशन, जॉबकार्ड सहित अन्य योजनाओं के प्रमाण पत्र व पंजीयन शिविर आयोजित कराये जा रहे हैं। उन्होंने आज के वृहद कार्यक्रम के लिए जनप्रतिनिधिगणों, स्वयं सेवी संस्थाओं व स्थानीय लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति विकास की मुख्य धारा का अंग नहीं बन जाता है।जनपद में जिलाधकारी

चोकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर अपराधों की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।एसपी ने मिशन सेफ प्यूचर अभियान के अंतर्गत स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि स्कूल बसों, ऑटो, ई-रिक्शा सहित सभी स्कूली वाहनों की नियमित जांच की जाए तथा उनकी फिटनेस, परमिट, बीमा, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए।सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनपद में संचालित सभी ई-रिक्शा चालकों के सत्यापन अभियान को तेज करने के निर्देश दिए।कहा कि

चालकों की पहचान, अभिलेखों और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए तथा संदिग्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में सामाजिक सौहार्द एवं

कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया।थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी संवेदनशील गतिविधि की सूचना मिलने पर तथ्यों का निष्पक्ष सत्यापन करते हुए विधि एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करें।साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक एवं अपातिजनक सूचनाओं पर लगातार निगरानी रखी जाए ताकि

वॉयस ऑफ लखनऊ 09

ई.सी.सी.ई. एजुकेटर्स के पद पर चयनित अम्यर्थियों की सूची जारी
बहराइच । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि जनपद बहराइच के परिषदीय विद्यालयों में अवस्थित को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में 140 ई.सी.सी.ई. एजुकेटर्स के चयन हेतु अंतिम तिथि के उपरान्त सेवायोजन पोर्टल पर उक्त पद हेतु 3173 आवेदन प्राप्त हुए थे। श्री सिंह ने बताया कि विकास भवन सभागार में जनपदीय चयन समिति की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों एवं संबंधित सेवाप्रदाता फर्म की उपस्थिति में रैण्डमाइजेशन प्रक्रिया संपादित की गयी जिसमें सेवायोजन पोर्टल पर प्राप्त 3173 आवेदन के संपेक्ष रैण्डमाइजेशन के उपरान्त कुल 420 अभ्यर्थी प्रदर्शित हुए।विकास भवन सभागार बहराइच में 16 से 19 जून 2026 तक एवं 22 जून 2026 को प्रमाण पत्र/अभिलेखों का परीक्षण/साक्षात्कार में सेवायोजन पोर्टल पर रैण्डमाइजेशन के उपरान्त प्रदर्शित 420 अम्यर्थियों के सोंपेक्ष मात्र 197 अधिकारियों में मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चोहान, उप जिलाधकारी पाली घनश्याम भारती, जिला प्रोबेशन अधिकारी नन्दलाल सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चन्द्र मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी डीएस दयाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

अध्यक्ष मनीष तिवारी, जिला पंचायत सदस्य अमर विश्वकर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे, अधिकारियों में मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चोहान, उप जिलाधकारी पाली घनश्याम भारती, जिला प्रोबेशन अधिकारी नन्दलाल सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चन्द्र मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी डीएस दयाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

अध्यक्ष मनीष तिवारी, जिला पंचायत सदस्य अमर विश्वकर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे, अधिकारियों में मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चोहान, उप जिलाधकारी पाली घनश्याम भारती, जिला प्रोबेशन अधिकारी नन्दलाल सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चन्द्र मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी डीएस दयाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

में नियमित वाहन चेकिंग अभियान चलाने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन जांच करने तथा राज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।एसपीने कहा कि ऐसे वाहनों से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और आमजन को परेशानी होती है, इसलिए इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में छात्र संगठनों एवं शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी गतिविधियों पर भी सतर्क निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एसपी ने यात्रा मार्गों, शिवालयों एवं प्रमुख स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, यातायात व्यवस्था सुचारु रखने तथा कांवड़ ?ों और आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट ने अयोध्या में तीन कॉलोनियों के जमीन अधिग्रहण रद्द करने से किया झुनकार

- 1965 का आवासपरिषद कानून बरकरार, भू-स्वामियों को 2013 भूमि अधिग्रहण कानून के समान लाभ देने होंगे: हाईकोर्ट**

विधि संवाददाता

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रावधानों की असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। हालांकि, इस अधिनियम के तहत जिन भू-स्वामियों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी, उन्हें मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के ऐसे लाभ दिए जाएंगे, जो निष्पक्ष प्रतिकर एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत मिलने वाले लाभों से कम नहीं होंगे। इसके साथ ही खंडपीठ ने अयोध्या के विकास के लिए प्रस्तावित आवास एवं विकास परिषद की तीन आवासीय योजनाओं को निरस्त करने से इन्कार कर दिया।

न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने जनहित याचिका सहित याचिकाओं के एक समूह का निस्तारण करते हुए 173 पृष्ठों का यह फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 28, 31, 32 और 55 की संवैधानिक वैधता तथा अयोध्या की तीन आवासीय योजनाओं के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने अधिनियम की धारा 28, 31 और 32 को वैध ठहराया, लेकिन कहा कि यदि धारा 55 और उससे संबंधित अनुसूची को वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में निहित सुरक्षा प्रावधानों को शामिल किए बिना लागू किया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन होगा। अदालत ने इन

प्रारवधानों को असंवैधानिक घोषित करने के बजाय उनकी ऐसी व्याख्या की, जिससे यह सुनिश्चित हो कि वर्ष 1965 के अधिनियम के तहत होने वाले प्रत्येक भूमि अधिग्रहण में भू-स्वामियों को वर्ष 2013 के अधिनियम के अनुरूप मौद्रिक मुआवजा, पुर्नर्वास एवं पुनर्स्थापन के लाभ मिलें। अदालत ने अयोध्या की तीनों आवासीय योजनाओं को निरस्त करने से इन्कार करते हुए कहा कि ये एक समेकित विकास परियोजना के हिस्सा हैं, जिन पर वर्ष 2020 से चरणबद्ध तरीके से कार्य चल रहा है। इन योजनाओं के लिए भूमि की व्यवस्था खरीद, लैंड पूलिंग और अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से की गई है। कई चरणों में अवाढ़ी पारित हो चुके हैं और अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा तीसरे पक्षों को भी आवंटित किया जा चुका है। ऐसे में इस स्तर पर योजनाओं को निरस्त करने से वर्षों की मेहनत, सार्वजनिक धन और व्यापक जनहित प्रभावित होगा। खंडपीठ ने आवास एवं विकास परिषद को निर्देश दिया कि वह वर्ष 2013 के अधिनियम के अनुरूप मुआवजे का निर्धारण कर उसका भुगतान करे तथा जहां आवश्यकता हो, वहां पहले से पारित अवाढ़ी की समीक्षा कर उन्हें भी इसी कानून के अनुरूप संशोधित किया जाए। अदालत ने परिषद को यह भी निर्देश दिया कि जिन भू-स्वामियों की पूरी भूमि या संपत्ति अधिग्रहित होने से वे पूर्ण रूप से विस्थापित हो गए हैं, उनकी पहचान कर छह माह के भीतर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 21 तथा वर्ष 2013 के अधिनियम के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी प्रावधानों एवं सिद्धांतों के अनुरूप पुनर्वास योजना तैयार कर लागू की जाए। साथ ही स्पष्ट किया कि मौजूदा संशोधित आवधिक से असंतुष्ट भू-स्वामी विधि के अनुसार उन्हें चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होंगे। भविष्य में 1965 के अधिनियम के तहत होने वाले सभी भूमि अधिग्रहण भी इसी निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप किए जाएंगे।

भारत में नहीं हुई ईंधन की किल्लत: पुरी

नयी दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि इस सालहोमूर्ज जलडमरूमध्य के बंद होने से आपूर्ति बाधाएँ पैदा होने के बावजूद भारत ने विविध स्रोतों, बढ़ी हुई रिफाईनिंग क्षमता और घरेलू उत्पादन के जरिए उपभोक्ताओं को किसी अभाव का सामना नहीं करने दिया।

पुरी ने कहा कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को केवल हाइड्रोकार्बन की उपलब्धता तक सीमित रखने के बजाय आयात के विविधीकरण, रणनीतिक साझेदारियों, बुनियादी ढांचे के विस्तार और वैकल्पिक ईंधनों जैसे व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है। उन्होंने कहा कि होमूर्ज जलडमरूमध्य के रास्ते जहाजों का आवागमन बाधित होने के बावजूद देश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू रही। पुरी ने कहा कि ईरान युद्ध शुरू होने से पहले भारत अपने कच्चे तेल का लगभग आधा आयात इसी मार्ग से जुड़े देशों से

संक्षेप

बस में हुए विस्फोट में 14 लोग घायल

जरमना (सीरिया)। सीरिया की राजधानी एक उपनगर में बृहस्पतिवार को हुए विस्फोट में 14 लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। हालाँकि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार रात को बताया था कि विस्फोट में दो लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को जारी एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि मलबे से बममद तीन कटेहुए अंगों के आधार पर मौत का आंकड़ा गलत तरीके से दर्ज कर लिया गया था। बयान के अनुसार, जांच के बाद यह पता चला कि ये अंग जिवित बचे मरीजों के हैं जिनकी सर्जरी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जरमना में धमाका एक मिनीवैन टैक्सी में लगाए गए विस्फोटक उपकरण के कारण हुआ। धमाके के समय टैक्सी में यात्री सवार थे।मिनबर अंसार अल-रसूल नामक एक कम चर्चित समूह ने एक बयान जारी कर झमेले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। सीरियाई अधिकारियों ने बम विस्फोट मामले में अब तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या जांच के नतीजों का घोषणा नहीं की है। जरमना में दूझ धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की बड़ी आबादी रहती है।यहां दूझ समुदाय के कुछ सदस्यों और देश की इस्लामवादी नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार का समर्थन करने वाले सुन्नी मुसलमानों के बीच तनाव रहा है।

इंटरटेनमेंट...

शूटिंग के दौरान रश्मिका मंधाना को लगी चोट

मुंबई। अभिनेत्री रश्मिका मंधाना ने पुष्टि की है कि अपनी आगामी फिल्म मायसा की शूटिंग के दौरान उनके दाहिने कूल्हे में चोट लग गई। अभिनेत्री ने बताया कि यह उनकी लगातार तीसरी चोट है। मंधाना ने सोमवार शाम इंस्टाग्राम पर अपनी सेहत को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। यह पोस्ट उन खबरों के बाद आई है, जिनमें कहा गया था कि डॉक्टरों ने उन्हें छह सप्ताह के पूर्ण आराम की सलाह दी है। उन्होंने लिखा, चोट लगना बहुत बुरा होता है। मैं चाहती थी कि किसी को इसके बारे में पता न चले, लेकिन अब सबको मालूम है। माफ कीजिए, मैं कुछ समय से गावब थी, लेकिन अब वापस आ गई हूं। यह कुछ समय पहले हुआ था और यह मेरी लगातार तीसरी चोट है। मुझे अपने शरीर को मंश्री न नहीं, ईशानी शरीर मानते हुए उसका ख्याल रखना सीखना चाहिए। अभिनेत्री ने बताया कि मायसा के एक डॉस सीकेंस की शूटिंग के दौरान उनके दाहिने कूल्हे से पैर को जोड़ने वाली टेंडन में से एक अलग हो गई।



उन्होंने कहा मेरे दाहिने कूल्हे की एक टेंडन अलग हो गई है। अब उसके दोबारा जुड़ने के बाद ही मैं सामान्य तरीके से पैर उठा पाऊंगी। यह

आवारापन-2 में इमरान हाशमी फिर निभायेंगे शिवम पंडित का किरदार



मुंबई। फिल्म आवारापन के 19 साल बाद अभिनेता इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में वापसी कर रहे हैं। विशेष फिल्म से बुधवार को फिल्म का ट्रेलर जारी किया। फिल्म के ट्रेलर में उअ और हालत से बदले शिवम की वापसी दिखाई

करता था, जबकि 90 प्रतिशत एलपीजी और 60 प्रतिशत गैस आयात भी इसी रास्ते से होता था। उन्होंने कहा कि आपूर्ति बाधित होने के बावजूद भारत ने स्रोतों में विविधता लाकर देश में कहीं भी कमी नहीं होने दी। उन्होंने कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक भी पेट्रोल पंप सूखा नहीं पड़ा। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत ने कच्चे तेल के आयात स्रोतों को 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है, जबकि पेट्रोल पंपों की संख्या 2014 के लगभग 52,000 से बढ़कर अब 1.07 लाख हो गई है। शहरी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार भी 55 क्षेत्रों से बढ़कर 309 तक हो गया है। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों से आयात में आई कमी की भरपाई के लिए घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया। पुरी ने कहा कि आज अमेरिका भारत के लिए एलपीजी



का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है, जो कुल आयात का लगभग 67 प्रतिशत है। मंत्री ने

कहा कि सरकार ने 84,000 करोड़ रुपये के समुद्र मंथन कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज को बढ़ावा देना है। इस योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी और सरकार डिलिंग लागत का 50 प्रतिशत या प्रति कुआँ 650 करोड़ रुपये तक मदद देगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने

कम्प्रेस्ड बायोगैस और एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल को खारिज करते हुए कहा कि 1.07 लाख पेट्रोल पंपों में से केवल चार मामलों में गड़बड़ी पाई गई, जो किसी व्यापक समस्या का संकेत नहीं है। मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर उपभोक्ताओं पर कम पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सीमित वृद्धि हुई, जिसे कर कटौती ने संतुलित कर दिया। भारत ने अब तक वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद खुद को काफी हद तक सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन वैश्विक चुनौतियाँ अभी बरकरार हैं। नई वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था सुरक्षित, स्मार्ट और टिकाऊ होनी चाहिए।

ई-कॉमर्स मंचों से बढ़ायी जा सकती है हथकरघा उत्पादों की वैश्विक पहुंच

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि देश का हथकरघा क्षेत्र बढ़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करता है और ई-कॉमर्स मंचों के माध्यम से इसके उत्पादों की वैश्विक पहुंच को और बढ़ाया जा सकता है।



राष्ट्रपति ने 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में लगभग 35 लाख लोग कार्यरत हैं, जिनमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह क्षेत्र देश के समावेशी विकास

और आत्मनिर्भरता की एक मजबूत नींव के रूप में काम करेगा। मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 भी प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि इस क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए नई प्रौद्योगिकियों का

उत्साह और कौशल इस क्षेत्र की दीर्घकालिक और बहुआयामी सफलता सुनिश्चित कर सके। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा उद्यमी, डिजाइनर और स्टार्टअप पारंपरिक हस्तशिल्प को आधुनिक रूझानों, ब्रांड और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जोड़कर नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

समुचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल समाधानों के जरिए बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, ई-कॉमर्स मंचों के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की वैश्विक बाजारों तक पहुंच को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है। मुर्मू ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार से लैस कई प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं और संस्थानों के माध्यम से युवाओं को सक्रिय सहयोग दिया जाना चाहिए, ताकि

यूक्रेन के ड्रेन हमले से रूस की एक ऑनलाइन खुदरा कंपनी के गोदाम में लगी आग



की चपेट में आए वाइल्डबेरीज के एक दर्जन से अधिक गोदाम जलकर खाक हो चुके हैं। यूक्रेन इन हमलों के जरिये रूस की जनता और

सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। क्षेत्रीय गवर्नर डेनिस पासलर ने बताया कि तीन डोन ने गोदाम की छत को निशाना बनाया।

अधिकारियों के अनुसार गोदाम से 800 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

चीन के निर्यात की वृद्धि दर घटी

बैकॉक। उच्च प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और वाहनों को मजबूत वैश्विक मांग के बावजूद जुलाई में चीन के निर्यात वृद्धि की रफ्तार पिछले महीने की तुलना में कुछ धीमी पड़ गई। सीमा शुल्क विभाग के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, जून में 125.6 अरब डॉलर रहा चीन का व्यापार अधिशेष जुलाई में घटकर 112.5 अरब डॉलर रह गया।



चीन का निर्यात जुलाई में सालाना आधार पर लगभग 24 प्रतिशत बढ़ा, जबकि इससे पिछले महीने जून में इसमें 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं, आयात जुलाई में सालाना आधार पर 27.5 प्रतिशत बढ़ा, जो जून में दर्ज

पश्चिम एशिया से एल्यूमीनियम की आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे चीन के एल्यूमीनियम निर्यात में वृद्धि हुई। व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि चीन अब मुख्य रूप से कम लागत वाले विनिर्माण से आगे बढ़कर उन्नत विनिर्माण के लिए आवश्यक मशीनरी और प्रमुख कलपुर्जों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है। जनवरी से जुलाई की अवधि के दौरान उच्च प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों का निर्यात एक वर्ष पहले की समान अवधि की तुलना में लगभग 41 प्रतिशत बढ़ा। इस दौरान वाहनों का निर्यात 55 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मशीनरी का कुल निर्यात 26 प्रतिशत बढ़ा।

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत, ब्रिक्स समूह की अलग मुद्रा शुरू करने के पक्ष में नहीं है और ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं करता है।

ब्रिक्स समूह में दुनिया की उभरती और विकासशील 11 अर्थव्यवस्थाएं - ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं। यह समूह वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श तथा सहयोग के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। जयपुर में ब्रिक्स देशों के व्यापार एवं उद्योग मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक के समापन के बाद गोयल ने संवाददाताओं से कहा, भारत ब्रिक्स मुद्रा के पक्ष में नहीं है। हम इसके पक्ष में नहीं हैं कि ब्रिक्स मुद्रा जैसी नयी योजना लाई जाय। भारत का उसपर



विरोध है। गोयल का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि वर्ष 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को अमेरिकी डॉलर के स्थान पर किसी अन्य मुद्रा को बढ़ावा देने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी थी।

पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स के सदस्य देश, खासकर रूस और चीन, अमेरिकी डॉलर के विकल्प की तलाश तथा अलग ब्रिक्स मुद्रा की संभावनाओं पर चर्चा करते रहे हैं। गोयल ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के बीच संतुलित व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा हुई। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए आसान तथा पर्याप्त वित्त उलब्ध कराने के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया।

मेलबर्न में दिखायी जायेगी हुमा की फिल्म बयान

नयी दिल्ली। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न (आईएफएफएम) में अपनी आगामी फिल्म बयान की प्रस्तुति से पहले कहा कि इस फिल्म में उनकी भूमिका बेहद चुनौतीपूर्ण और



संतोषजनक रही है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विकास रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में हुमा रूही नाम की एक दृढ़ निश्चयी पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं, जो यौन उत्पीड़न के आरोपी एक प्रभावशाली नेता से जुड़े मामले की जांच करती है। उन्होंने एक बयान में कहा रूही एक ऐसी महिला है, जो भारी दबाव के बीच भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहती है। इस किरदार को निभाते हुए मुझे एक अभिनेत्री के रूप में कई तरह से अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का मौका दिया है। इस फिल्म की रोमांचक जांच-पड़ताल की कहानी के साथ-साथ सत्ता, सच और न्याय से जुड़े सवालों ने मुझे इसे करने के लिए आकर्षित किया।

ब्लूप्लाइ में रसेल क्रो के साथ दिखेंगी प्रियंका



लॉस एंजिल्स। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा फिल्म ब्लूफ्लाय में अभिनेता रसेल क्रो के साथ नजर आएंगी। द ब्लफ की अभिनेत्री ने बृहस्पतिवार को अपने इंस्टाग्राम हैडल पर एक पोस्ट

के जरिए यह खबर साझा की। पोस्ट में उन्होंने समाचार वेबसाइट डेडलाइन में छपे लेख की तस्वीर भी साझा की थी। उन्होंने इसके साथ लिखा, अब अगली फिल्म की ओर। डेडलाइन के

BABU BANARASI DAS EDUCATIONAL GROUP

NAAC Accredited

NBA ACCREDITED

BBD UNIVERSITY
Host University for KHELO INDIA

12500+ More than **1500+** Companies have already hired our Students!

Job offers & still continuing since last 4 years ...

150000+ Alumni

ADMISSION OPEN 2026-2027

BBD UNIVERSITY | www.bbdun.ac.in

COURSES OFFERED

- Engineering
- Management
- Legal Studies
- Pharmacy
- Architecture
- Dental Science
- Computer Applications
- Basic Sciences
- Education
- Hotel Management
- Agricultural Sciences
- Media & Communication
- Ph.D. in all Disciplines

Meritorious Scholarships Offered

Courses available in Collaboration with **IBM** and **HCL GUVI**

NEW COURSES

Courses in Collaboration with **HCL GUVI**
B.TECH (CSE) Generative AI | MBA- DS & AI | IMBA- DS & AI
BBA - Marketing | M.TECH (CSE) - AI

BBD CODS | **BDS Bachelor of Dental Surgery** (4 Year Course & 1 Year Rotatory Internship) | **M.D.S/Ph.D.** (in all 9 Specialties)

BBD ITM | **AKTU CODE - 054** | www.bbditm.ac.in

B.TECH [CSE, CSE(AI), CSE(AI&ML), CSE(DS),IT,ECE, ME, EE,CE] **MBA & M.TECH**

BBD NIIT | **AKTU CODE - 056** | www.bbdniit.ac.in

B.TECH [CSE,CSE(AI&ML),CSE(AI),IT,ECE, EE, ME,CE] **M.TECH, MBA**
B.PHARM. M.PHARM. D.PHARM BTEUP CODE- 2746

SCHOLARSHIP @25%

All 4 Years in EE, ME, CE and ECE in AKTU Colleges

AMENITIES

- Auditorium (1000+ Seating Capacity)
- Student's Mail & Cafeteria
- Transport & Health Services
- Lord Siddhi Ganesh Temple
- In Campus Bank and ATM
- AC & Non-AC Hostels
- BCCI Approved Cricket Stadium
- BBD 90.8FM Channel
- 24x7 Security & Wifi Campus

TOP RECRUITERS

amazon Google IBM adani zomato accenture tcs Microsoft Infosys HARMAN PAYTM EY Capgemini NEWGEN wipro pwc

BBD Green City, Ayodhya Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226028 India.

www.bbdu.ac.in 0522-6196300/6196222